NEERAJ®

Serving Education for Last 40 Years

M.H.I. - 107

भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास-2 (C. 1700-2000)

(History of Indian Economy-2 [C. 1700-2000])

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Ved Prakash Sharma*

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 300/-

Content

भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास-2 (C. 1700-2000)

(History of Indian Economy-2 [C. 1700-2000])

Question Paper—June-2024 (Solved) 1
Sample Question Paper—1 (Solved) 1
Sample Question Paper—2 (Solved) 1
Sample Question Paper—3 (Solved) 1
Sample Question Paper—4 (Solved) 1

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

खंड-1 इतिहासलेखन और अर्थव्यवस्था (Historiography and Economy)

1. भारतीय इतिहास में अठारहवीं शताब्दी 1
(The Eighteenth Century in Indian History)
2. औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहासलेखन 8
(Historiography of the Colonial Economy)

खंड-2 व्यापार एवं बाजार (Trade and Markets)

3. व्यापारी एवं बाजार : 1757-1857 15
(Merchants and Markets: 1757-1857)
4. उपनिवेशवाद और व्यापार : 1857-1947 22
(Colonialism and Trade: 1857-1947)

खंड-3 ग्रामीण अर्थव्यवस्था (The Rural Economy)

5. कृषि नीति और भू-अधिकार 28
(Agrarian Policy and Land Rights)
6. वाणिज्यीकरण का स्वरूप 35
(Patterns of Commercialisation)
7. कृषि अर्थव्यवस्था : विकास और ठहराव का प्रश्न 41
(Agrarian Economy: The Question of Growth and Stagnation)

खंड-4 औपनिवेशिक अर्थशास्त्र (Colonial Economy)

8. मुद्रा व्यवस्था (Currency System) 47
9. धन निकासी विवाद (Drain of Wealth Dabate) 54
10. औपनिवेशिक अर्थशास्त्र और इसके प्रभाव 59
(Colonial Economy and its Impact)
11. अकाल और महामारी 68
(Famines and Epidemics)

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

खंड-5 वन तथा सामुदायिक भूमि (Forests and Commons)

12. वन तथा जनजातीय अर्थव्यवस्थाएँ 75
(Forests and Tribal Economies)

13. जनजातीय समाज और औपनिवेशक अर्थव्यवस्था 80
(Tribal Societies and Colonial Economy)

खंड-6 जनसांख्यिकीय तथा अर्थव्यवस्था (Demography and Economy)

14. औपनिवेशक भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन और कृषक समाज 86
(Demographic Change and Agrarian Society in Colonial India)

खंड-7 शिल्प उत्पादन, तकनीकी परिवर्तन और औद्योगीकरण (Craft Production, Technological Change and Industrialization)

15. निरौद्योगीकरण : विभिन्न दृष्टिकोण 93
(The De-Industrialization Appraches)

16. शिल्प उद्योग और लघु-स्तरीय उत्पादन 100
(Crafts Industries and Small Scale Production)

17. औद्योगीकरण का स्वरूप (Patterns of Industrialization) 106

18. भारतीय पूँजीपति वर्ग का उदय 113
(Emergence of the Indian Capitalist Class)

19. औपनिवेशिक भारत में श्रम (Labour in Colonial India) 119

20. महिलाएं तथा श्रम (Women and Labour) 125

21. तकनीकी, विज्ञान और साम्राज्य (Technology, Science and Empire) 133

खंड-8 स्वातंत्र्योत्तर भारत की अर्थव्यवस्था (Economy of Post-Independence India)

22. योजना तथा विकास (Planning and Development) 140

23. भूमि तथा काश्तकारी सुधार (Land and Tenancy Reforms) 145

24. कृषि तथा उद्योग (Agriculture and Industry) 151

25. आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा उद्योग 160
(Growth of Modern Banking System, Nationalisation of Banking and Industries)

खंड-9 उदारीकरण की ओर (Towards Liberalisation)

26. वैश्वीकरण (Globalisation) 167

27. उदारीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था 172
(The Political Economy of Liberalisation)

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास-2 (C. 1700-2000)

M.H.I.-107

(History of Indian Economy-2 [C. 1700-2000])

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग से कम-से-कम दो प्रश्न अवश्य कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक* ***समान*** *हैं।*

भाग - I

प्रश्न 1. '18वीं सदी अराजकता और उथल-पुथल की सदी थी' परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-1, पृष्ठ-2, प्रश्न 1

प्रश्न 2. ब्रिटिश भारत सरकार की भूमि नीति का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-5, पृष्ठ-29, प्रश्न 1

प्रश्न 3. 'भारतीय मुद्रा प्रणाली का उद्देश्य औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना था।' विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-8, पृष्ठ-49, प्रश्न 4

प्रश्न 4. औपनिवेशिक काल के दौरान महामारी पर एक नोट लिखिए। महामारी के प्रति औपनिवेशिक सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी?

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-11, पृष्ठ-64, 'महामारी की विपदा', 'अकाल', महामारी और औपनिवेशिक नीतियां'

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(क) सूरत का पतन

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-3, पृष्ठ-16, 'सूरत का पतन'

(ख) पैन-एशियाई बाजार अर्थव्यवस्था

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-4, पृष्ठ-25, प्रश्न 5

(ग) पूर्व-औपनिवेशिक जनजातीय अर्थव्यवस्था

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-13, पृष्ठ-81, प्रश्न 1

(घ) प्रारंभिक जनगणना

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-14, पृष्ठ-86, 'आरंभिक जनगणना'

भाग - II

प्रश्न 6. ''भारत के पारम्परिक उद्योगों के पतन का अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है।'' औद्योगीकरण की बहस के आलोक में इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-16, पृष्ठ-102, प्रश्न 1

प्रश्न 7. औपनिवेशिक भारत में भारतीय पूँजीपति वर्ग के उद्भव और विकास का पता लगाइए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-18, पृष्ठ-114, प्रश्न 2

प्रश्न 8. औपनिवेशिक भारत में महिलाओं की रोजगार क्षमता की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-20, पृष्ठ-126, प्रश्न 2

(घ) 1950-1980 की औद्योगिक नीति के केन्द्र बिन्दु क्या थे?

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-24, पृष्ठ-151, 'उद्योग'

प्रश्न 10. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(क) भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में औपनिवेशिक हस्तक्षेप के प्रति भारतीय प्रक्रिया

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-21, पृष्ठ-135, प्रश्न 2

(ख) बैंकों का राष्ट्रीयकरण

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-25, पृष्ठ-160, 'बैंकों का राष्ट्रीयकरण और वित्तीय संस्थानों का विकास'

(ग) बिड़ला बन्धु

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-17, पृष्ठ-107, 'बिड़ला ब्रदर्स'

(घ) भूमण्डलीकरण

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-26, पृष्ठ-167, 'वैश्वीकरण'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS

Sample

QUESTION PAPER - 1

(Solved)

भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास-2 (C. 1700-2000)

M.H.I.-107

(History of Indian Economy-2 [C. 1700-2000])

समय : 3 घण्टे] *[कुल अंक : 100*

नोट : *निम्नलिखित में से कोई पाँच प्रश्न करें। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

प्रश्न 1. "अठारहवीं शताब्दी सार्वभौमिक रूप से अवनति की शताब्दी थी।" टिप्पणी कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-2, प्रश्न 1

प्रश्न 2. 19वीं शताबदी के उत्तरार्द्ध में भारतीय व्यापार के बदलते स्वरूप का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-4, पृष्ठ-23, प्रश्न 1

प्रश्न 3. वाणिज्यीकरण क्या है? क्या आप मानते हैं कि वाणिज्यीकरण का प्रारंभ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ हुआ?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-36, प्रश्न 1

प्रश्न 4. ब्रिटिश-भारतीय सरकार की मुद्रा नीति पर चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-8, पृष्ठ-48, प्रश्न 1

प्रश्न 5. 'प्रारंभिक औपनिवेशिक नीति संरक्षण की बजाए व्यावसायिक जरूरतों से नियंत्रित थी'। टिप्पणी कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-12, पृष्ठ-76, प्रश्न 1

प्रश्न 6. एफ.टी.जे.ई. को परिभाषित कीजिए। निरौद्योगीकरण के रोजगार पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-15, पृष्ठ-97, प्रश्न 4

प्रश्न 7. पूर्व-औपनिवेशिक श्रमिकों की काम की स्थितियों पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-19, पृष्ठ-120, प्रश्न 2

प्रश्न 8. भारत की स्वतंत्रता के बाद योजना विशेषज्ञों द्वारा जिन समस्याओं का तत्काल सामना करना पड़ा, उनकी चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-22, पृष्ठ-141, प्रश्न 1

प्रश्न 9. वे कौन-से संरचनात्मक दबाव थे, जिनका परिणाम 1991 के आर्थिक संकट में निकला?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-26, पृष्ठ-167, प्रश्न 1

प्रश्न 10. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–

(क) आंतरिक व्यापार तंत्र

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-4, पृष्ठ-22, 'आंतरिक व्यापार तंत्र'

(ख) पट्टेदारी सुधार

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-29, 'पट्टेदारी सुधार'

(ग) काउंसिल बिल

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-8, पृष्ठ-48, 'काउंसिल बिल'

(घ) राष्ट्रवादी और धन निकासी

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-9, पृष्ठ-54, 'राष्ट्रवादी और धन निकासी'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास-2
(*C.* 1700-2000)
(History of Indian Economy-2 [*C.* 1700-2000])

भारतीय इतिहास में अठारहवीं शताब्दी
(The Eighteenth Century in Indian History)

1

परिचय

भारत ने 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के अफगान आक्रमणों, मराठा विस्तार और आंतरिक कलह के प्रति संवेदनशीलता के कारण उथल-पुथल भरा युग देखा। राजकोषीय गिरावट और राजनीतिक अव्यवस्था के कारण साम्राज्य का पतन तेज हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अराजकता का फायदा उठाया और धीरे-धीरे औपनिवेशिक प्रभुत्व स्थापित किया। इस अवधि का इतिहासलेखन धार्मिक कट्टरता या नैतिक पतन के सरलीकृत आख्यानों को खारिज करते हुए साम्राज्य के पतन पर बहस को दर्शाता है। इसके बजाय, यह प्रणालीगत विफलताओं, आर्थिक संकटों और स्थानीय पुनरुत्थान पर जोर देता है। लखनऊ और बंगाल जैसे क्षेत्रीय राज्यों में सांस्कृतिक जीवन शक्ति पनपी। कंपनी की एक राजनीतिक शक्ति में परिवर्तन, उपनिवेशवाद की जड़ों और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर बहस जारी है।

अध्याय का विहंगावलोकन

अठारहवीं शताब्दी की प्रमुख विशेषताएँ

भारत में 18वीं शताब्दी में दो महत्त्वपूर्ण महत्त्व परिवर्तन हुए। सबसे पहले, मुगल साम्राज्य आंतरिक संकटों के कारण क्षेत्रीय संस्थाओं में विभाजित हो गया, जबकि समवर्ती रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी (1757) और बक्सर (1763) के युद्ध के बाद सत्ता में आई और एक व्यापारिक इकाई से एक शासक शक्ति में बदल गई। इस शताब्दी को अब 'लंबी' शताब्दी के रूप में देखा जाता है, जो 1680 के दशक से मुगल विघटन के साथ शुरू हुई और 1820 के दशक तक विस्तारित हुई, जिसमें प्रमुख राजनीतिक पुनर्गठन हुए। आर्थिक रूप से, कंपनी के प्रभुत्व से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, क्षेत्रीय विकास जारी रहा। इसके अतिरिक्त, इस शताब्दी को समझने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के एकीकरण पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें हिंद महासागर का व्यापार यूरोपीय प्रभावों के बीच आर्थिक गतिशीलता को आकार दे रहा है।

अठारहवीं शताब्दी संबंधी वाद-विवाद

18वीं शताब्दी के भारत में गहन परिवर्तन हुए, जिससे विविध व्याख्याएं सामने आईं। इतिहासकार मोटे तौर पर दो खेमों में विभाजित हैं—1750 से पहले साम्राज्य-केन्द्रित बनाम क्षेत्र-केन्द्रित दृष्टिकोण और 1750 के बाद भारतवादी बनाम यूरोपीयवादी दृष्टिकोण। साम्राज्य-केन्द्रित विचार मुगल साम्राज्य के पतन को उजागर करते हैं, अराजकता और शिकारी संरचनाओं पर जोर देते हैं। क्षेत्र-केन्द्रित दृष्टिकोण स्थानीय एजेंसी पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, जो स्वायत्त राज्यों और विपक्षी राजनीति के उदय पर प्रकाश डालते हैं। यूरोपीयवादी दृष्टिकोण अराजक भारत पर यूरोप की विजय पर जोर देते हैं, जबकि भारतवादी दृष्टिकोण ब्रिटिश शासन को आकार देने में भारत की एजेंसी पर जोर देते हैं। भारतवादी व्यावसायिक विकास के बीच गहरी निरंतरता के लिए तर्क देते हैं। 18वीं शताब्दी के पतन के बजाय परिवर्तन की अवधि के रूप में देखते हैं। यह सूक्ष्म समझ गिरावट और असंतोष की पारंपरिक कहानियों को चुनौती देती है।

मुगल साम्राज्य, उसका पतन और अठारहवीं शताब्दी का प्रारंभ

मुगल साम्राज्य का पतन नैतिक पतन या कमजोर शासकों की धारणाओं को खारिज करते हुए विभिन्न व्याख्याओं का विषय है। इरफान हबीब राजकोषीय संकट और गुटीय संघर्ष पर जोर देते हैं, जबकि सतीश चंद्र और अथर अली जागीर व्यवस्था की खामियों पर प्रकाश डालते हैं। जॉन रिचर्ड्स साम्राज्य एकीकरण की विफलता के लिए तर्क देते हैं। मार्शल हॉगसन का सुझाव है कि तकनीकी अंतराल ने साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। इक्तिदार आलम खान राज्य और प्रजा दोनों को सशक्त बनाने में बारूद की दोहरी भूमिका को दर्शाते हैं। स्टुअर्ट गॉर्डन विविध भर्ती के माध्यम से मराठों की सैन्य सफलता को दर्शाता है। संरचनात्मक

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

और संयोजक मुद्दों ने गिरावट को और बढ़ा दिया, जिससे केन्द्र और क्षेत्रों के बीच एक जटिल परस्पर क्रिया का पता चला, जो शक्ति की गतिशीलता और राजकोषीय तनाव में उतार-चढ़ाव की विशेषता थी।

क्षेत्रीयकरण की प्रक्रिया

एक क्षेत्र-केन्द्रित परिप्रेक्ष्य मुगल साम्राज्य के पतन की विविध व्याख्याओं को प्रकट करता है। आंद्रे विंक आंतरिक तोड़फोड़ पर प्रकाश डालते हैं, जबकि स्टीफन ब्लेक इसे एक रस्सी संतुलन अधिनियम के रूप में चित्रित करते हैं। एम.एन. पियर्सन सैन्य आकांक्षाओं के साथ पितृसत्तात्मक शासन के बीच सामंजस्य बिठाने में विफलता का तर्क देते हैं। मुजफ्फर आलम स्थानीय अभिजात वर्ग द्वारा लगातार तोड़फोड़ दर्शाते हैं। राज्य से आने वाले दबावों में गुटबाजी और स्थानीय अभिजात वर्ग का एकीकरण शामिल था। क्षेत्रीय अभिजात वर्ग की सामाजिक स्थिति अलग-अलग थी, वे वित्तीय और सैन्य माध्यमों से महत्त्वपूर्ण प्रभाव रखते थे। उन्होंने विविध शासनों का गठन किया-'उत्तराधिकारी' राज्य, मराठों और जाटों जैसी स्वतंत्र राजनीति और स्थानीय रियासतें। इस गतिशीलता ने पूरे भारत में राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया, जिससे विविध शासन और सत्ता संघर्ष हुए।

इन क्षेत्रीय राज्यों की प्रकृति कितनी 'मुगल' थी?

हाल के अध्ययन 18वीं शताब्दी के उत्तर भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक परिवर्तनों को उजागर करते हैं, जिससे मुगल शासन से अर्ध-स्वायत्त राज्यों में क्रमिक परिवर्तन का पता चलता है। मुगल प्रशासनिक रूपों को अपनाने के बावजूद, दक्कन, अवध और बंगाल के नवाबों जैसे क्षेत्रीय शासकों ने संशोधन पेश किए। उन्होंने जागीरदारी प्रणाली को बदल दिया, कार्यकारी और राजकोषीय शक्तियों को समेकित किया और बढ़ते बैंकिंग नेटवर्क द्वारा सुगम राजस्व खेती को अपनाया। क्षेत्रीय केंद्रों ने राजनीतिक शक्ति की गतिशीलता को नया आकार देते हुए बैंकिंग पूँजी को आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय भागीदारी, विशेष रूप से ब्रिटिश, बढ़ी, जिसने सैन्य और वित्तीय सहायता के माध्यम से क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित किया। स्वदेशी और यूरोपीय तत्वों के बीच इस जटिल परस्पर क्रिया ने 18वीं शताब्दी के भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया।

अठारहवीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था

18वीं शताब्दी के भारत से जुड़ी आर्थिक बहसें दो मुख्य मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती हैं। सबसे पहले, आर्थिक स्वरूप के क्षेत्रीयकरण ने सवाल उठाया कि क्या यह विस्तार, संकट या ठहराव का संकेत था। दूसरे, प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान परिवर्तन में व्यवधान देखे गए, हालांकि कुछ को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था। जबकि बंगाल और अवध में संक्रमण अपेक्षाकृत शांतिपूर्वक हुआ। पंजाब और दक्कन में व्यवधान उत्पन्न हुआ, विशेषकर मराठा गतिविधियों के कारण। मुगल साम्राज्य के पतन पर बहस के बावजूद, सबूत मिश्रित आर्थिक स्थितियों का सुझाव देते हैं। शहरी विकास अलग-अलग रहा, कुछ कु क्षेत्रों में प्रगति हुई, जबकि अन्य में गिरावट आई। विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ, विशेषकर यूरोप के साथ, जिससे आर्थिक जीवन शक्ति में योगदान हुआ। राजस्व अधिकतमीकरण द्वारा चिह्नित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ने व्यापार पैटर्न को बदल दिया, लेकिन भारत के आर्थिक परिदृश्य में कोई विशेष बदलाव नहीं आया। स्वदेशी बैंकिंग प्रणालियाँ कायम रहीं और सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1780 के दशक में, चीन के साथ अंग्रेजी व्यापार, विशेष रूप से निजी व्यापार, लगातार विस्तारित हुआ, 1752 और 1799 के बीच बंगाल में निजी व्यापार 7.6% से बढ़कर 41.88% हो गया। इस वृद्धि को भारतीय फाइनेंसरों के निवेश से बढ़ावा मिला, खासकर कलकत्ता में एजेंसी हाउसों में और बम्बई, अफीम और कपास व्यापार का समर्थन करते हुए। दक्षिणी भारत में, हालांकि कंपनी के वित्त में बैंकरों की भूमिका स्पष्ट नहीं थी, व्यापारी-फाइनेंसरों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुबाशेस और चेट्टी व्यापारियों सहित विभिन्न समूहों ने कंपनी की वित्तीय सहायता में योगदान दिया।

अठारहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था : उभरते परिवर्तन

प्रारंभिक उपनिवेशवाद के तहत भारत के आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद, इसे केवल विनाश के माध्यम से देखना गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीतियों का उद्देश्य स्थायी बंदोबस्त की तरह, अपने वाणिज्य के लिए बंगाल के राजस्व को स्थिर करना था। हालांकि इसने निजी संपत्ति का विस्तार किया, इसने 1790 के बाद कृषि संकट को बढ़ा दिया। ग्रामीण स्तरीकरण बढ़ा, जिससे जमींदारों और जोतदारों को लाभ हुआ। दक्षिण भारत में, मिरासदारों ने मजदूरों का शोषण करके ग्राम ठेकेदारों के रूप में सत्ता हासिल की। कारीगरों और बुनकरों पर कंपनी के कठोर नियंत्रण के कारण असुरक्षा पैदा हुई। इसके बावजूद, कुछ कारीगर आंतरिक बाजार में फले-फूले। हालांकि कंपनी द्वारा सालाना £4 मिलियन की अनुमानित संपत्ति की निकासी ने भारत के आर्थिक उपनिवेशीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे यूरोपीय लोग समृद्ध हुए, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाया।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. "अठारहवीं शताब्दी सार्वभौमिक रूप से अवनति की शताब्दी थी।" टिप्पणी कीजिए।

उत्तर–इस दावे की सूक्ष्म जाँच की आवश्यकता है कि अठारहवीं शताब्दी सार्वभौमिक गिरावट का काल थी, विशेष रूप से प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के तहत भारत के संबंध में। जबकि पारंपरिक आख्यान अक्सर विनाश और क्षय पर जोर देते हैं। करीब से देखने पर ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव से आकार लेने वाली अधिक जटिल वास्तविकता का पता चलता है। सबसे पहले, यह स्वीकार

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

करना महत्त्वपूर्ण है कि भारत में कंपनी की उपस्थिति केवल विनाश से चिह्नित नहीं थी। जबकि उनकी व्यापारिक नीतियों का उद्देश्य उनके वाणिज्य को बढ़ावा देना था, उन्होंने ऐसे बदलाव भी प्रस्तुत किए, जिन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त ने कंपनी के राजस्व को स्थिर करते हुए निजी संपत्ति अधिकारों का विस्तार किया। हालांकि इसकी कीमत चुकानी पड़ी, जिससे 1790 के बाद कृषि संकट और बढ़ गया। कृषि कीमतों में गिरावट ने कई किसानों को असुरक्षित बना दिया, जो कंपनी के हस्तक्षेप के नकारात्मक पक्ष को उजागर करता है।

इसी तरह, दक्षिण भारत में, कंपनी की कार्रवाइयों ने नकद लेन-देन को बढ़ाया और मिरासदारों की शक्ति को मजबूत किया, जिन्होंने खेती को राजस्व खेती के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। इससे कम विशेषाधिकार प्राप्त समूहों के लिए आर्थिक और सामाजिक अधीनता में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, कारीगरों और बुनकरों के प्रति कंपनी के कठोर व्यवहार और उनकी एकाधिकारवादी प्रथाओं ने कई लोगों को कीमतों और मांग में उतार-चढ़ाव के प्रति असुरक्षित बना दिया। फिर भी, यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि कुछ कारीगर आंतरिक बाजार में सफलता प्राप्त करते हुए, व्यवस्था को नेविगेट करने में कामयाब रहे।

इन चुनौतियों के बावजूद, पूरी शताब्दी को सार्वभौमिक गिरावट के रूप में चित्रित करना अत्यधिक निराशावादी होगा। विशेष रूप से बंगाल के उत्तरी किनारों और उसके मुहाने पर कृषि सुधार में विकास और लचीलेपन के क्षेत्र थे। जबकि कंपनी की नीतियों ने जमींदारों और जोतदारों की स्थिति को मजबूत किया, ग्रामीण स्तरीकरण में वृद्धि हुई और कुछ लोग 'कुलक-जमींदारों' के रूप में भी विकसित हुए, जो ऋण प्रदान करते थे और स्थानीय कृषि व्यापार में संलग्न थे।

इसके अलावा, जबकि कंपनी के हस्तक्षेप ने भारत की अर्थव्यवस्था को व्यापार और उत्पादन के वैश्विक चक्रों से बांध दिया। इसने कुछ के लिए वाणिज्यिक अवसरों का भी विस्तार किया, भले ही दूसरों की कीमत पर। भारतीय व्यापारियों, बैंकरों और फाइनेंसरों ने इन अवसरों का लाभ उठाया, हालांकि अक्सर व्यापक आबादी के लिए सीमित लाभ के साथ। हालांकि कंपनी की प्रथाओं के कारण भारत से ब्रिटेन की ओर धन की निकासी ने आर्थिक चुनौतियों को बढ़ा दिया, जिससे भारत को अपने उपनिवेश को सब्सिडी देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

इन जटिलताओं के बावजूद, यह स्पष्ट है कि कंपनी की नीतियों का भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा और अक्सर हानिकारक प्रभाव पड़ा। जबकि कुछ व्यक्ति और समूह इन परिवर्तनों को पार करने और यहां तक कि समृद्ध होने में कामयाब रहे। कई अन्य लोगों को बढ़ी हुई भेद्यता और शोषण का सामना करना पड़ा। कंपनी की एकाधिकारवादी प्रथाओं और धन की निकासी ने आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया, जिससे निर्भरता और शोषण का चक्र कायम हो गया।

प्रश्न 2. 'साम्राज्य केन्द्रित' दृष्टिकोण की समालोचना कीजिए। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि अठारहवीं शताब्दी 'अराजकता और अव्यवस्था' से पूर्ण शताब्दी थी?

उत्तर–ऐतिहासिक काल, विशेष रूप से अठारहवीं शताब्दी को समझने के लिए 'साम्राज्य-केन्द्रित' दृष्टिकोण मुख्य रूप से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी साम्राज्य शक्तियों के कार्यों और नीतियों पर केन्द्रित है। प्राय: यह दृष्टिकोण राजशाही संस्थाओं द्वारा प्रभुत्व, शोषण और कभी-कभी अराजकता को उजागर करता है। एक आलोचनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि हालांकि राजशाही कार्रवाइयों ने वास्तव में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन पूरी शताब्दी को 'अराजकता और अव्यवस्था' के रूप में चित्रित करना इस खेल में जटिल गतिशीलता को अधिक सरल बनाता है।

जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीतियों और हस्तक्षेपों के निस्संदेह गंभीर परिणाम थे, जिनमें आर्थिक शोषण और सामाजिक उथल-पुथल भी शामिल थी। यह पहचानना आवश्यक है कि यह शताब्दी समान रूप से अराजकता से चिह्नित नहीं थी। इसके बजाय, इसमें निरंतरता, परिवर्तन और प्रतिरोध का मिश्रण देखा गया।

उदाहरण के लिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त साम्राज्य-केन्द्रित दृष्टिकोण का प्रतीक है, क्योंकि यह कंपनी के लिए राजस्व को स्थिर करने के उद्देश्य से साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षाओं का एक उत्पाद था। हालांकि इसके कार्यान्वयन से कृषि संकट पैदा हुआ और सामाजिक असमानताएँ बढ़ीं, जो साम्राज्यवादी नीतियों के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। बहरहाल, लचीलेपन और अनुकूलन के क्षेत्र उभरे, क्योंकि कुछ किसानों और व्यापारियों ने नए आर्थिक परिदृश्य में कदम रखा।

इसी तरह, दक्षिण भारत में, कंपनी के हस्तक्षेपों ने नकद लेन-देन को बढ़ाया और कुछ सामाजिक समूहों की शक्ति को मजबूत किया, जिससे दूसरों के लिए अधीनता बढ़ गई। यह साम्राज्य-केन्द्रित दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रभुत्व और शोषण पर जोर देता है। हालांकि यह पहचानना आवश्यक है कि प्रतिरोध और अनुकूलन भी प्रचलित थे। उदाहरण के लिए, मिरासदारों ने बदलती परिस्थितियों के बीच एजेंसी का प्रदर्शन करते हुए खेती को राजस्व खेती के साथ जोड़ा। जबकि कंपनी के कार्यों ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक व्यापार चक्रों से बांध दिया और असमानताओं को बढ़ा दिया। उन्होंने कुछ व्यक्तियों और समूहों के लिए अवसर भी पैदा किए। भारतीय व्यापारियों, बैंकरों और फाइनेंसरों ने व्यापक सामाजिक हितों की कीमत पर इन अवसरों का फायदा उठाया। यह सूक्ष्म समझ एक समान अराजकता की धारणा को चुनौती देती है और भारतीय समाज के भीतर विविध अनुभवों पर जोर देती है।

साम्राज्य-केन्द्रित दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार करने की भी आवश्यकता

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

होती है, जो ऐतिहासिक काल की अधिक सूक्ष्म समझ प्रदान करते हैं। जबकि साम्राज्यवादी कार्रवाइयों ने निस्संदेह समाजों के प्रक्षेप पथ को आकार दिया। अन्य कारकों, जैसे-स्वदेशी एजेंसी, सांस्कृतिक गतिशीलता और क्षेत्रीय विविधताओं ने भी इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन जटिलताओं को नजरंदाज करने से ऐतिहासिक आख्यानों को अतिसरलीकृत करने और गैर-साम्राज्यवादी अभिनेताओं की एजेंसी और लचीलेपन को नजरंदाज करने का जोखिम है। इसके अलावा, संपूर्ण अठारहवीं शताब्दी को 'अराजकता और अव्यवस्था' के दौर के रूप में प्रदर्शित करना स्थिरता, नवीनता और सांस्कृतिक उत्कर्ष के काल को नजरंदाज कर देता है। जबकि कुछ क्षेत्रों और समुदायों को निस्संदेह उथल-पुथल का सामना करना पड़ा, दूसरों ने अपेक्षाकृत शांति और समृद्धि का अनुभव किया।

प्रश्न 3. अठारहवीं शताब्दी का अध्ययन क्षेत्रीय राज्यों में गुंजायमान सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में कीजिए।

उत्तर—सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के जीवंत केन्द्र के रूप में उभर रहे क्षेत्रों के संदर्भ में अठारहवीं शताब्दी को देखने के लिए एक सूक्ष्म समझ की आवश्यकता है, जो साम्राज्य-केन्द्रित कथा से परे हो। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी साम्राज्यवादी शक्तियों की कार्रवाइयों का निस्संदेह महत्त्वपूर्ण प्रभाव था, उस समय के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में स्थानीय समुदायों, व्यापारियों और सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं की एजेंसी और गतिशीलता को पहचानना आवश्यक है।

अठारहवीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विविध सामाजिक-आर्थिक गतिविधियाँ चल रही थीं। साम्राज्यवादी हस्तक्षेपों और व्यापारिक नीतियों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, कुछ क्षेत्रों में स्वदेशी अभिनेताओं और स्थानीय गतिशीलता द्वारा संचालित जीवंत आर्थिक गतिविधियाँ देखी गईं।

उदाहरण के लिए, बंगाल में, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाए गए स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य कंपनी के लिए राजस्व को स्थिर करना था, लेकिन इससे कृषि संकट और सामाजिक उथल-पुथल पैदा हो गई। हालांकि इन चुनौतियों के बीच, स्वदेशी व्यापारियों, बैंकरों और फाइनेंसरों ने वाणिज्यिक अवसरों के विस्तार पर पूँजी लगाई। छोटे कुलीनों और महान कुलीनों द्वारा समर्थित बाजारों के उद्भव ने आर्थिक आदान-प्रदान और विकास के रास्ते तैयार किए। इसके अतिरिक्त, कृषि सुधार परियोजनाओं और नए बाजारों की स्थापना ने किसानों को व्यापक बाजारों के साथ अधिक आसानी से जुड़ने में सक्षम बनाया, जिससे जमीनी स्तर पर आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिला।

इसी तरह, दक्षिण भारत में, कंपनी के हस्तक्षेप का उद्देश्य नकद लेन-देन को बढ़ाना और कुछ सामाजिक समूहों की शक्ति को मजबूत करना था। हालांकि मिरासदारों जैसे स्थानीय समुदायों ने खेती को राजस्व खेती और स्थानीय कृषि प्रबंधन के साथ जोड़कर लचीलेपन का प्रदर्शन किया। यह दर्शाता है कि कैसे स्वदेशी अभिनेताओं ने बदलती परिस्थितियों को अपनाया और अपने क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को चलाना जारी रखा।

इसके अलावा, स्वदेशी फाइनेंसरों, व्यापारियों और उद्यमियों ने व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिण भारत में, दुबाशेस, चेट्टी व्यापारियों और ब्राह्मण इजारादारों ने कंपनी के व्यापार और वित्तपोषण कार्यों के समर्थन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह, बंगाल में, भारतीय फाइनेंसरों ने चीन को अफीम और कपास के बढ़ते व्यापार का समर्थन करने के लिए तैयार धन ऋण प्रदान किया और एजेंसी घरानों में निवेश किया। इन स्वदेशी कलाकारों ने न केवल व्यापार के विस्तार में योगदान दिया, बल्कि अपने क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को बनाए रखने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसके अलावा, अठारहवीं शताब्दी में पूरे भारत में जीवंत आर्थिक केन्द्रों और बाजार कस्बों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में, बाजार शहरी वाणिज्य, भूमि स्वामित्व और राजस्व खेती के हलचल भरे केन्द्रों के रूप में विकसित हुए, जिससे व्यापक स्तर के लोगों को आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने के अवसर मिले। इस विकेन्द्रीकृत आर्थिक परिदृश्य ने स्थानीय उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा दिया, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं की समग्र जीवंतता में सहयोग मिला।

इसके अतिरिक्त, बंगाल में रेशम उद्योग जैसे कुछ आर्थिक क्षेत्रों की लचीलापन और अनुकूलनशीलता उल्लेखनीय है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतार-चढ़ाव और कंपनी के हस्तक्षेप के बावजूद, बाजार की गतिशीलता में बदलाव के बावजूद रेशम उत्पादन जारी रहा। यह लचीलापन बाहरी दबावों के बीच क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बनाए रखने में स्थानीय उद्योगों और आर्थिक गतिविधियों के महत्त्व को दर्शाता है।

प्रश्न 4. अठारहवीं शताब्दी के संदर्भ में इतिहासकारों की क्षेत्र-केन्द्रित विचारधारा का परीक्षण कीजिए।

उत्तर—अठारहवीं शताब्दी की जाँच में इतिहासकारों द्वारा अपनाया गया क्षेत्र-केन्द्रित दृष्टिकोण इस अवधि के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषता वाले विविध सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्यों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करके, इतिहासकार सूक्ष्म आख्यानों को उजागर कर सकते हैं, जो स्थानीय समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली अद्वितीय गतिशीलता, चुनौतियों और अवसरों को उजागर करते हैं।

क्षेत्र-केन्द्रित दृष्टिकोण की प्रमुख शक्तियों में से एक भारत के विभिन्न हिस्सों में ऐतिहासिक अनुभवों की विविधता और जटिलता को उजागर करने की क्षमता है। बंगाल, दक्षिणी भारत और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में प्रत्येक की सामाजिक-आर्थिक संरचना, राजनीतिक गतिशीलता और साम्राज्यवादी हस्तक्षेपों के प्रति प्रतिक्रियाएँ अलग-अलग थीं। इन विशिष्ट क्षेत्रों पर जूम करके, इतिहासकार स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं, सामाजिक संबंधों और शक्ति

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com